प्रस्ताव

37 आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। लेबल लगाना। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश — अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार

आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। लेबल लगाना। पहल अधिनियम।

- उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए पेश किए गए कच्चे या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पर लेबल लगाने की मांग करता है यदि इन्हें निर्दिष्ट तरीकों से बदली गई आनुवंशिक सामग्री के साथ पौधों या जानवरों से बनाया गया है।
- ऐसे भोजन, या अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को ''प्राकृतिक'' के रूप में लेबल करने या विज्ञापित करने से प्रतिबंधित करता है।
- उन खाद्य पदार्थों को छूट देता है जो: प्रमाणित कार्बनिक हैं; अनजाने में आनुवंशिक रूप से तैयार की गई सामग्री के साथ तैयार किए गए हैं; ऐसे जानवरों से तैयार किए गए हैं जिन्हें आनुवंशिक रूप से तैयार की गई सामग्री खिलायी गई है लेकिन जो खुद आनुवंशिक रूप से तैयार नहीं किए गए हैं; चिकित्सकीय समस्याओं के इलाज के लिए दिए जाते हैं; तुरंत खाए जाने के लिए बेचे जाते हैं जैसे कि किसी रेस्तरां में; या अल्कोहल वाले पेय पदार्थ।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने को नियंत्रित करने के लिए कुछ लाख डॉलरों से लेकर $1 मिलियन तक के बढ़े हुए वार्षिक राज्य खर्चे।
- इस उपाय की ज़रूरतों के संभावित उल्लंघन से उत्पन्न मुक़दमेबाज़ी के कारण राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए संभावित खर्चे, लेकिन जिनके अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है। इन खर्चों में से कुछ को अदालत में दायर की जाने वाली फीसों से समर्थन मिलेगा जो कि प्रत्येक कानूनी मामले में शामिल पक्ष को मौजूदा कानून के तहत देने की ज़रूरत होगी।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

जिनेटिकली इन्जीनियर्ड (GE) खाद्य पदार्थ। आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसी जीवित जीव की विशेषताओं में कुछ वांछित फेरबदल करने के लिए उस जीव की आनुवंशिक सामग्री को बदलने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पौधे और जानवर की नयी प्रजातियां विकसित करने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है जो बाद में खाद्य पदार्थों के स्रोतों के रूप में उपयोग में आती हैं, इन्हें GE खाद्य पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का बहुधा इस्तेमाल कीटों के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने अथवा उन्हें ऐसा बनाने के लिए किया जाता है कि वे कीटनाशकों के उपयोग के बाद भी बरकरार रहें। सबसे आम GE फसलों में मक्का और सोयाबीन शामिल हैं। सन 2011 में, अमेरिका में उत्पादित कुल मक्के का 88 प्रतिशत और सोयाबीन का 94 प्रतिशत GE बीजों से हुआ। अन्य प्रचलित GE फसलों में रिजका, राई, कपास, पपीता,चुकंदर, और जुचीनी शामिल हैं। इसके अलावा GE फसलों का उपयोग खाद्य सामग्रियों (जैसेकि उच्च फलशर्करा कार्न सिरप) को बनाने में किया जाता है जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो कच्चे कृषि फसल नहीं हैं) में अक्सर शामिल किये जाते हैं। किन्ही आकलनों के अनुसार, कैलीफोर्निया में किराने की दुकानों में बिकने वाले खाद्य उत्पादों के 40 से 70 फीसदी में कुछ GE सामग्रियां होती हैं।

संघीय विनियमन। GE खाद्य पदार्थों के विनियमन की विशेष जरूरत संघीय कानून को नहीं होती। हालांकि, अमेरिकी कृषि विभाग ने अभी उन GE फसलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है जो दूसरों पौधों के लिए हानिकारक हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन की जिम्मेदारी इस बात को सुनिश्चित करना है कि ज्यादातर खाद्य पदार्थों (इस बात की परवाह किए बिना कि वे आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए हैं) और खाद्य पदार्थ एडिटिव सुरक्षित हैं और उनपर उचित लेबल लगाया गया है।

राज्य विनियमन। मौजूदा राज्य कानून के तहत, कैलीफोर्निया एजेंसियों के खास तौर पर जरूरत नहीं है कि वे GE खाद्य पदार्थों का विनियमन करें। हालांकि, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हैल्थ (DPH) ज्यादातर खाद्य पदार्थों के विनियमन और उनपर लेबल लगाने के लिए जिम्मेदार है।

प्रस्ताव

यह उपाय GE खाद्य पदार्थों के विनियमन के लिए स्पष्ट तौर पर जरूरी कई बदलाव राज्य कानून में करता है। खास तौर पर यह, (1) इस बात की जरूरत बताता है कि बेचे जाने वाले अधिकतम GE खाद्य पदार्थों पर ठीक तरीके से लेबल लगे हों, (2) इस प्रकार के खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने के विनियमन के लिए DPH की जरूरत बताता है, और (3) व्यक्तियों को स्वीकृति देता है कि वे इस उपाय के लेबल लगाने के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले खाद्य पदार्थ निर्माताओं पर मुकदमा करें।

खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाना। यह उपाय इस बात की जरूरत बताता है कि राज्य में खुदरा बिकने वाले GE खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट

37

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

रूप से आनुवंशिक रूप से तैयार का लेबल लगा हो। विशेष तौर पर, यह उपाय इस बात की जरूरत बताता है कि आनुवंशिक रूप से पूरी तौर पर या आंशिक रूप से तैयार कच्चे खाद्य पदार्थों (जैसे फल और सब्जियां) पर आगे पैकेज या लेबर पर शब्द "आनुवंशिक रूप से तैयार" का लेबल लगा होना चाहिए। यदि वस्तु को अलग से पैकेज नहीं किया गया है या इसपर कोई लेबल नहीं लगा है, तो ये शब्द उस आलमारी या डिब्बे पर जरूर नजर आने चाहिए जहां इसे बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है। उपाय इस बात की जरूरत भी बताता है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जरिए पूरी तौर पर या आंशिक रूप से उत्पादित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर "आनुवंशिक तौर पर आंशिक रूप से उत्पादित" अथवा "आंशिक तौर पर आनुवंशिक तरीके से उत्पादन संभव" का लेबल लगा हो।

खुदरा विक्रेता (जैसे कि किराने की दुकानें) इस उपाय का पालन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके खाद्य उत्पादों पर सही तरीके से लेबल लगा हुआ है। GE लेबल लगे उत्पाद स्वीकृत होंगे। प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए जिसपर GE लेबल नहीं हो, खुदरा विक्रेता को सामान्यतया यह जरूर लिखना होगा कि उत्पाद को लेबल लगाने से छूट क्यों मिली। खुदरा विक्रेता मुख्यतः दो तरीकों से उत्पाद को छूट मिलने के संबंध में लिख सकता हैः (1) उत्पाद प्रदाता (जैसेकि एक थोक विक्रेता) से शपथ वक्तव्य प्राप्त करके जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उत्पाद को आनुवंशिक रूप से जानबूझ कर या चतुराई से तैयार नहीं किया गया है या (2) एक स्वतंत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करके कि उत्पाद में GE सामग्री नहीं मिली हुई है। पूरी खाद्य आपूर्ति शृंखला में अन्य संस्थाएं (जैसे किसान और खाद्य पदार्थ निर्माता) भी इन रिकार्डों को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। यह उपाय कुछ खास खाद्य उत्पादों को भी उपरोक्त लेबल लगाने की जरूरत से बाहर रखता है। उदाहरण के तौर पर, मादक पेय, जैविक खाद्य पदार्थ, और रेस्तरां का भोजन तथा तत्काल खाए जाने वाले अन्य तैयार खाद्य पदार्थों को लेबल लगाने की जरूरत नहीं होती। पशु उत्पादों—जैसकि गोमांस या मुर्गा—जिनका उत्पादन सीधे तौर पर आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जरिए नहीं हुआ हो उन्हें भी छूट मिलेगी इस बात की परवाह किए बगैर कि उन्हें GE फसलें खिलाई गई थीं।

इसके अतिरिक्त, यह उपाय GE खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने और उनके विज्ञापन में इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है जैसेकि "प्राकृतिक", "प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया," "प्राकृतिक रूप से उगाया गया," और "पूरा प्राकृतिक"। जिस तरह से यह उपाय लिखा गया है उसे देखते हुए, इस बात की संभावना है कि इन प्रतिबंधों की व्याख्या अदालतें इस तरह करें कि ये कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर लागू होता है इस बात की परवाह किए बगैर कि वे आनुवंशिक रूप से तैयार की गई हैं।

राज्य विनियमन। इस उपाय के तहत GE खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने की जरूरतों का विनियमन DPH द्वारा किया जाएगा क्योंकि यह इसकी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और लेबलिंग को विनियमित करने की मौजूदा जिम्मेदारी का हिस्सा है। उपाय अपने द्वारा निर्धारित नियमों को अपनाने की अनुमति विभाग को देता है जो उपाय को लागू करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, DPH को उन नियमों को बनाने की जरूरत होगी जो सैंपलिंग प्रक्रिया का वर्णन करते हों इस बात के निर्धारण के लिए कि खाद्य पदार्थों में GE सामग्रियां हैं।

उपाय लागू करने के लिए मुकदमा। उपाय का उल्लंघन करने पर राज्य, स्थानीय, अथवा निजी पार्टियों द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। यह अदालत को यह अनुमति देता है कि वह जांच और अभियोग कार्रवाई में आए सभी उचित खर्चों को इन पार्टियों को दिलाए। इसके अतिरिक्त, यह उपाय स्पष्ट रूप से बताता है कि उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता कानूनी उपाय अधिनियम के तहत जरूरी उपायों के उल्लंघन के लिए मुकदमा कर सकते हैं। यह कानून उपभोक्ताओं को अनुमति देता है कि उनके मुकदमे में कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए किसी विशेष नुकसान का प्रदर्शन किए जाने की जरूरत नहीं है।

वित्तीय प्रभाव

राज्य प्रशासनिक खर्चे में वृद्धि। इस उपाय के परिणामस्वरूप GE खाद्य पदार्थों की लेबलिंग को दुरुस्त करने में DPH के लिए राज्य पर अतिरिक्त खर्च आएगा, जैसे कि यह निर्धारित करने के लिए दस्तावेजों की समीक्षा करना और नियमित अंतराल पर निरीक्षण करवाना कि खाद्य पदार्थ क्या वास्तव में सही लेबल के साथ बेचे जा रहे हैं। इस बात पर निर्भर करते हुए कि विभाग इन नियमों को कैसे और किस स्तर तक लागू करता है (जैसे कि किराना दुकानों का निरीक्षण यह कितने अंतराल पर करता है), इनके खर्चे **कुछ लाख डालर से $1 मिलयन सालाना से ज्यादा तक हो सकते हैं।**

मुकदमेबाजी से जुड़े खर्चे में संभावित वृद्धि। जैसा ऊपर वर्णन किया गया है, यह उपाय व्यक्तियों को लेबल लगाने की जरूरतों के उल्लंघन के लिए मुकदमे की अनुमति देता है। जैसे ही यह राज्य अदालतों में दायर मुकदमों की संख्या बढ़ाएगा, राज्य और काउंटी अतिरिक्त मामलों की प्रक्रिया और सुनवाई के लिए अतिरिक्त खर्च वहन करेंगे। इन खर्चों की सीमा दायर मुकदमों की संख्या, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा दायर मुकदमों की संख्या, और इनका फैसला अदालत ने कैसे किया इस बात पर निर्भर करेगी। बढ़े हुए अदालत के खर्चे में से कुछ भरपाई अदालत में मुकदमा दायर करने की फीस से हो जाएगी जो प्रत्येक मामले में शामिल पार्टियों को मौजूदा कानून के तहत देना होगा। अदालत के कुल खर्चों के संदर्भ में इन खर्चों के लम्बे समय तक महत्वपूर्ण रहने की संभावना नहीं है।

प्रस्ताव 37 के पाठ के लिए, पृष्ठ 110 देखें।